भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2100
उत्तर देने की तारीख-19/03/2025

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने हेतु प्रयास

2100 **श्रीमती संगीता यादवः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा विगत पांच वर्षों में, भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2047 तक, विशेष रूप से समावेशी मानव विकास और नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई रूपरेखा या कार्य योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या मंत्रालय वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का उनके संभावित योगदान के आधार पर मूल्यांकन कर रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): दिनांक 29.07.2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 **(**एनईपी 2020) 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। इस नीति में एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव है**,** जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण करते हुए एसडीजी-4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है।

एनईपी 2020 में भारतीय लोकाचार पर आधारित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराके भारत को एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे, और इस प्रकार भारत को

एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाए। इस दिशा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।

साथ ही, एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप बेहतर शिक्षा के लिए अनुसंधान को मुख्य आवश्यकता के रूप में मान्यता देते हुए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी तालमेल को बढ़ावा देना भी है।

शिक्षा मंत्रालय देश के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू कर रहा है, जिसमें प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना (पीएमआरएफ), प्रभावशाली अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी (इम्प्रिंट), भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च (स्ट्राइड), अनुसंधान और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (स्पार्क), नेशनल इनीशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन (एनआईडीआई) और विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स) शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम-उषा का लक्ष्य राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त पोषित करना है ताकि 'अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता सुधार' सहित समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

"मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन के लिए "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्रों" के संबंध में बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के पैरा 60 के अनुसरण में, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि के दौरान 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्त परिव्यय के साथ स्वास्थ्य, कृषि और दीर्घकालिक शहरों के क्षेत्रों में एक-एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को अनुमोदित किया है। इसके अतिरिक्त, 500 करोड रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र को बजट भाषण 2025-26 में शामिल किया गया है।

भारत को वर्ष **2047** तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी **2020** के साथ जोड़ा गया है।

*****